



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 1978/माघ 27, 1899

No 79]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 1978/MAGHA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेश

नई, दिल्ली 16 फरवरी, 1978

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th February, 1978

फा० आ० 100(अ) —भारत सरकार के भूमपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० फा० आ० 137 (असा०)/18क/आई डी आर ए/73, तारीख 12 मार्च, 1973 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात ऐग्रो-इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है), मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लि०, विश्वमित्रि, बटौरा नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाले पात्र वर्ष की अवधि के लिए, ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश करती है कि उक्त आदेश 12 मार्च, 1978 से एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[सं० फा० 4/1/73-मी० यू० मो०]

S.O. 100(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 137(E)/18A/IDRA/73 dated the 12th March, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) authorised the Gujarat Agro-Industries Corporation Limited, Ahmedabad (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over the management of the whole of the industrial undertaking, namely, M/s. Hindustan Tractors Limited, Vishwamitri, Baroda, for a period of five years commencing from the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order continue to have effect for a further period of one year.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year from the 12th March, 1978.

[No. F. 4/1/73-CUC.]

आदेश

ORDER

का० आ० 101(अ)—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश म० का० आ० 250 (असा०)/18 चख/आई डी आर ए/73, तारीख 26 अप्रैल, 1973 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी करने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापन, पचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से संबंधित दायित्वों से भिन्न), जिनका हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड, विश्वमित्र, बड़ौदा, नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम की स्वामी कम्पनी एक पक्षकार है, या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू किए जा सकते हैं, का प्रवर्तन उक्त आदेश के जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश का० आ० 261 (असा०)/18 चख/आई डी आर ए/74, तारीख 24 अप्रैल, 1974, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश का० आ० 173 (असा०)/18 चख/आई डी आर ए/75, तारीख 9 अप्रैल, 1975, और का० आ० 309 (असा०)/18 चख/आई डी आर ए/76, तारीख 22 अप्रैल, 1976 तथा उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश का० आ० 298 (असा०)/18 चख/आई डी आर ए/77, तारीख 23 अप्रैल, 1977 द्वारा उक्त आदेश 11 मार्च, 1978 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 25 अप्रैल, 1978 तक की ओर अवधि के लिए बढ़ा देनी चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 25 अप्रैल, 1978 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की ओर अवधि के लिए बढ़ाती है।

[सं० फा० 4/1/73-सी० य० सी०]

जी० वी० रामाकृष्ण, अपर सचिव

S.O. 101(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 250(E)/18FB/IDRA/73 dated the 26th April, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of the sub-section (1) of section 18 FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order (other than liabilities relating to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as the Hindustan Tractors Limited, Vishamitri, Baroda or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from the date of issue of the said Order and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas by the orders of the Government of India in the Ministry of Industrial Development S.O. 26(E)/18FB/IDRA/74 dated the 24th April, 1974, Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) S.O. 173(E)/18FB/IDRA/75 dated the 9th April, 1975, and S.O. 309(E)/18FB/IDRA/76 dated the 22nd April, 1976 and in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) S.O. 298(E)/18FB/IDRA/77 dated the 23rd April, 1977, the said Order was extended for the period upto and inclusive of the 11th March, 1978;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto 25th April, 1978;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18 FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of 25th April, 1978.

[No. F. 4/1/73-CUC]

G. V. RAMAKRISHNA, Addl. Secy.